Middle East are likely to get Their 50 50 basis is a comparatively much less profitable basis on the whole than ours because there are no tax laws there It gives us much more money than you envisage

**Shri Joachim Alva:** The Burmah-Shell, which is the backbone of the Assam Oil Company, has only recently announced its terms and conditions to the Pakistan Petroleum Company I want to know whether the Government will watch the situation and demand better terms from this Company even in the preparatory stage as we have made more progress in oil than Pakistan

**Shri K. D. Malaviya:** Yes, Sir We propose to demand much better terms than what are now being negotiated there or anywhere

**Shrimati Tarkeshwari Sinha:** May I know whether it is a fact that the Assam Oil Company has agreed to prepare the project reports for the refineries and when they are likely to prepare the project reports If they are not preparing the project report, may I know who is going to submit project reports to the Government of India?

**Shri K. D. Malaviya:** The foreign consultants are now busy examining the question of preparing the project report for both the refineries The A O C. are only helping in the pipe-line project

**Shri Narayanankutty Menon:** May I know whether, in view of the fact that this Rupee Company is going to trade purely in oil which is derived from the Indian wells, Government will stipulate a condition that the price of the crude oil, which is to be supplied to the company, will be entirely fixed in relation to the *cost of production* in India?

**Shri K. D. Malaviya:** We are still negotiating with the Assam Oil Company regarding the price that is to be fixed for the production of crude oil.

## राष्ट्रीय अनुशासन योजना

*९७३. { श्री भक्त दर्शन :
श्री दामानी :

क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मन्त्री २७ मई, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ४२८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) सभी वर्गों की शिक्षा संस्थाओं में राष्ट्रीय अनुशासन योजना चालू करने के सम्बन्ध में इस बीच क्या प्रगति हुई है, और

(ख) किन-किन राज्यों ने अपने अपने क्षेत्रों में योजना को (१) स्वीकार कर लिया है और (२) जारी किया है ?

**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** (क) इस योजना को पंजाब, बम्बई और पश्चिमी बंगाल के तीन क्षेत्रों में उन स्कूलों पर लागू करने का विचार है जिनको पुनर्वास मन्त्रालय से सहायता नहीं मिल रही या जो विस्थापित छात्रों के लिए नहीं चलाये जा रहे हैं। इस योजना के वित्तीय मामलों और प्रशासन सम्बन्धी ब्यौरों का अभी परीक्षण किया जा रहा है। आशा की जाती है कि इस योजना को इस वर्ष के दौरान में कार्यान्वित किया जायेगा ।

(ख) विस्थापित विद्यार्थियों के स्कूलों के विषय में सम्बन्धित तीनों राज्य सरकारों ने इस योजना को स्वीकार कर लिया है। इस योजना को अन्य स्कूलों में लागू करने के सम्बन्ध में राज्य सरकारों को शीघ्र ही लिखा जाएगा ।

**Some Hon. Members:** In English also

**Dr. K. L. Shrimali :** (a) It is proposed to extend the Scheme in three regions in Punjab, Bombay and West Bengal to schools other than those financed by the Ministry of Rehabilitation or run for displaced students.

The financial implications and the administrative details are still under examination It is hoped to implement the Scheme this year

(b) The Scheme has already been accepted by the Governments of the three States in question in regard to displaced students' schools Regarding the extension of the Scheme to other schools, the State Governments will be addressed shortly

**Mr. Speaker:** Now whenever a question is put in Hindi the answer is also given in Hindi In future copies of the answer in English to Hindi questions will be given in advance to the Notice Office Hon Members who want to put supplementary questions to questions in Hindi may look into that beforehand instead of asking the hon Minister to read it again in English on the floor of the House This is the parctice I intend adopting in future

**श्री भक्त दर्शन** क्या यह सत्य नही है कि हमारे माननीय प्रधान मत्री जी इस राष्ट्रीय अनुशासन योजना के बडे प्रबल समर्थक हैं और अनेक महान विदेशी अतिथियो ने उस की बडी प्रशसा की है । फिर इस मे इतनी शिथिलता क्यो की जा रही है और इसे तेजी से आगे क्यो नही बढ़ाया जा रहा है ?

**डा० का० ला० श्रीमाली** प्रधान मत्री इसी स्कीम के लिए नही, सभी अच्छे कामो के प्रति रुचि प्रदर्शित करते हैं ।

**Mr. Speaker:** Shri Damani

**श्री नवल प्रभाकर** क्या मैं जान सकता हू कि इस योजना के सम्बन्ध में दिल्ली प्रशासन से पूछा गया है ?

**Mr. Speaker:** When I call an hon Member what is the point in his keeping quiet and allowing another hon Member to stand up and put questions?

**श्री भक्त दर्शन** मेरे प्रश्न का उत्तर नही दिया गया । मैं यह जानना चाहता हू कि लगभग पिछले तीन वर्षों से इस योजना पर विचार किया जा रहा है और हमेशा यही उत्तर मिल रहा है कि कुछ दिनो में इसे लागू किया जाएगा, तो वे कौन सी खास अडचनें हैं जिन की वजह से इसे अभी तक अमल में नही लाया जा रहा है ।

**डा० का० ला० श्रीमाली** अडचने तो कुछ आर्थिक किस्म की ही है । प्लैनिंग कमिशन से जितना रुपया मिलना चाहिए था उतना उस के लिए मिल नही पाया है । चूकि सारे देश मे इस की व्यवस्था करना था, इसलिए बिना धन के यह काम चलाया नही जा सकता था । बहुत कोशिश करने पर अब परिस्थिति यह है कि इस वर्ष मेरे ख्याल से २० लाख रुपया उपलब्ध होगा, जिस मे से ७ लाख रु० तो मिनिस्ट्री आफ एजूकेशन देगी और १३ लाख रु० शायद मिनिस्ट्री आफ रिहैबिलिटेशन से मिलेगा । बात यह है कि प्लैनिंग कमिशन की योजना पहले बन चुकी थी, उस मे इस स्कीम की कोई जगह नही है । अब इसके लिए विशेष रुपया लेना है, और इसके लिए विशेष तरह की कठिनाइया हैं । लेकिन इस का प्रयत्न किया जा रहा है कि चूकि यह उपयोगी स्कीम है इसलिए जितनी जल्दी हो सके, इस का विस्तार किया जाए ।

**श्री भक्त दर्शन** क्या मैं जान सकता हूं कि केवल तीन राज्यो में ही इसको लागू करने का विचार क्यो किया जा रहा है और अन्य राज्यो मे इसको कब प्रारम्भ किया जायगा?

**डा० का० ला० श्रीमाली** जब इसके लिए पर्याप्त धन उपलब्ध हो जायेगा तब इसको आगे बढ़ाया जा सकेगा ।

**Shri Ranga:** In view of the fact that already for several decades the high schools as well as the colleges have been maintaining staff for giving physical training to their students and that there are separate periods set apart and that training is being given, is anything being done in order to see that these two things are co-related

in such a way that there is economy and also there is no confusion?

**Dr. K. L. Shrimali:** Yes, every effort will be made to co-ordinate the activities which are already being conducted in the educational institutions and those under this scheme.

**Shri Thimmaiah:** May I know whether there is any central body trying to teach in this national discipline scheme and extend the scheme to all the States?

**Dr K L. Shrimali:** No, Sir

## वेतन में स्वेच्छा से कटौती

*९७४ { श्री विभूति मिश्र :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री याज्ञिक :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के मंत्रियो, उप मंत्रियो और कुछ कर्मचारियो ने अपने वेतनो मे स्वेच्छा से कटौती करने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) क्या सरकार ने ये कटौतियां स्वीकार कर ली है ;

(ग) क्या ये कटौतियां स्थायी हैं ; और

(घ) इनसे कुल कितनी वार्षिक बचत होगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) तथा (ख). मंत्री परिषद के सदस्य अपने वेतन तथा भत्तो में स्वेच्छा से दस प्रतिशत की कटौती करने को राजी हो गए हैं। इस पर उन्होने अमल करना भी शुरू कर दिया है। अपने वेतनों में स्वेच्छा से कटौती करने का प्रस्ताव अभी सरकारी कर्मचारियों की किसी भी श्रेणी से प्राप्त नही हुआ है।

(ग) चूंकि यह कटौती स्वेच्छा से की गई है इसलिए इसके स्थायी अथवा अस्थायी रहने का प्रश्न ही नही उठता ।

(घ) लगभग एक लाख रूपए प्रति वर्ष

**Some Hon. Members:** In English also

**Shri Datar:** (a) and (b) Members of the Council of Ministers have voluntarily agreed to a ten per cent. cut in their salaries and allowances. It has already been brought into effect. No offer of a voluntary cut in their salaries has so far been received from any class of Government employees.

(c) The cut being a voluntary one, the question of its being permanent or otherwise does not arise.

(d) About one lakh per annum.

**श्री विभूति मिश्र** : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि राष्ट्रपति जी ने भी अपने वेतन मे से १० परसेंट कटाया है और विभिन्न प्रदेशो के मंत्रियो और उप-मंत्रियो ने भी दस परसेंट कटाया है ?

**श्री दातार** : राष्ट्रपति जी ने और उपराष्ट्रपति जी ने ऐसा किया है । मुझे मध्य प्रदेश के बारे मे मालूम नही है ।

**श्री विभूति मिश्र** मैं ने विभिन्न प्रदेश कहा था, मध्य प्रदेश नही ।

**श्री दातार** राज्य सरकारो के गवर्नरो ने कटौती को स्वीकार किया है । मंत्रीमंडल ने भी किया है ऐसी मेरी आशा है ।

**श्री प० ला० बारूपाल** : क्या मैं जान सकता हू कि भारत सरकार द्वारा जो भत्ता भूतपूर्व राजाओ को दिया जाता है उसमें से किसी नरेश ने कटौती स्वीकार की है ?

**Shri Datar:** It is a different matter. This relates to a cut in salaries, not a cut in privy purses.

**Shri Sonavane:** What are the reasons that prompted Government employees who are drawing more than Rs. 1,000 not to offer even one per cent cut in their salaries?